राजस्थान को अपने हिस्से का जल मिलेगा, जल प्रबंधन को मजबूती देगा- भजनलाल

सीआर पाटिल व नायब सिंह के साथ उन्होंने यमुना जल परियोजना के एमओए को अंतिम रूप दिया

नई दिल्ली/जयपुर, 23 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल परियोजना से संबंधित बैठक में भाग लिया। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही, किशाऊ बांध परियोजना से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, यमुना जल परियोजना को प्रभावी एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत, पानी को पारंपरिक नहर प्रणाली की बजाय, पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे जल संरक्षण सुनिश्चित होने के साथ ही वितरण व्यवस्था अधिक व्यापक बनेगी।

उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े छह राज्यों के मुद्दों का भी समाधान हो गया है और शीघ्र ही उससे संबंधित एमओए भी किया जाएगा। इससे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित, अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना राजस्थान, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जल्द ही राजस्थान को अपने हिस्से का पानी प्राप्त होगा, जिससे किसानों, उद्योगों और आमजन को व्यापक लाभ मिलेगा। साथ ही, प्रदेश में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में भी सहायता मिलेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रेणुका, लखवार और किशाऊ परियोजनाओं के क्रियान्वयन से मिलने वाले पानी से राजस्थान तथा दिल्ली के साथ ही, हरियाणा के लोगों को भी फायदा मिलेगा।

- **जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि इस परियोजना में पारंपरिक नहर प्रणाली की बजाय पाइप लाइन से पानी पहुँचाना प्रस्तावित है। इससे जल संरक्षण सुनिश्चित होगा तथा वितरण व्यवस्था व्यापक बनेगी।**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।**

दान राशि में कथित गबन की चर्चाओं के बीच राम मंदिर ने व्यवस्थायें बदलीं

अयोध्या, 23 जून। राम मंदिर की दानराशि में कथित गबन और चोरी के मामले सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान गणना और प्रबंधन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दान गणना कक्ष में प्रवेश करने वाले कर्मियों के लिए बिना जेब वाले विशेष वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

मोबाइल फोन, बैग, झोला, पर्स और अन्य निजी सामान लेकर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, प्रवेश और निकासी के समय कर्मियों की जांच भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, दानपात्रों से निकलने वाली नकदी की गणना के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या छह से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। गणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जा रही है और कई स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत गणना कक्ष में जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। गणना से पहले और बाद में कर्मियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। पूरी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।

मंदिर प्रशासन की ओर से किए गए ये बदलाव उस समय सामने आए हैं, जब दानराशि में अनियमितताओं को लेकर एसआईटी जांच चल रही है।

- **दान गणना कक्ष में प्रवेश करने वाले कर्मियों को अनिवार्य रुप से बिना जेब वाले विशेष वस्त्र पहनने होंगे**

एसओजी ने प्रयोगशाला सहायक परीक्षा की ओएमआर शीट में फर्ज़ीवाड़ा पकड़ा

फर्ज़ी तरीके से अंक बढ़वाकर चयन सूची में शामिल दो अभ्यर्थी गिरफ्तार

- **ओएमआर शीट की स्कैनिंग का कार्य करने वाली अधिकृत एजेंसी से कार्मिकों ने 27 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में अनुचित तरीके से कांट-छांट कर उनके अंक बढ़ा दिए और उन्हें अनंतिम चयन सूची में शामिल करा दिया।**

जयपुर, 23 जून। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाही करते हुए, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में हुए ओएमआर शीट फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने फर्जी तरीके से अंक बढ़वाकर चयन सूची में शामिल हुए दो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि जिन अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक महज 2 और 4 थे, उन्हें ओएमआर शीट में हेरफेर कर 165 और 191 अंक दिलाकर चयनित करा दिया गया था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 से जुड़े मामले में एसओजी थाना में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। अनुसंधान के दौरान पता चला कि परीक्षा की ओएमआर शीट स्कैनिंग का कार्य करने वाली अधिकृत एजेंसी राभव लिमिटेड के कार्मिकों ने अभ्यर्थियों से मिलीभगत कर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया था।

जांच में सामने आया कि एजेंसी के कार्मिक विनोद कुमार गौड़ और शादान खान ने कुल 27 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में अनुचित तरीके से कांट-छांट कर उनके अंक बढ़ा दिए और उन्हें अनंतिम चयन सूची में शामिल करवा दिया। एसओजी इस मामले में पहले ही विनोद कुमार गौड़, शादान खान तथा कंपनी के कार्यकारी निदेशक रामप्रवेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

एसओजी के अनुसार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संदेह के आधार पर मूल ओएमआर शीटों की दोबारा स्कैनिंग करवाई गई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

जांच में पाया गया कि करौली जिले के टोडाभीम थाना क्षेत्र के गांव नांगललाट निवासी महेन्द्र कुमार मीना (31) के प्राप्तांक स्कैनिंग के दौरान बढ़ाकर 165 अंक दर्शा दिए गए थे। जबकि मूल ओएमआर शीट की पुनः स्कैनिंग में उसके वास्तविक अंक मात्र 4 पाए गए।

वहीं, दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम नादना निवासी देवेन्द्र सिंह गुर्जर (28) के अंक स्कैनिंग के दौरान बढ़ाकर 191 दर्शाए गए थे। पुनः जांच में उसके वास्तविक अंक केवल 2 पाए गए।

एसओजी के अनुसार, इस फर्जीवाड़े के जरिए अनंतिम रूप से चयनित हुए अन्य 25 संदिग्ध अभ्यर्थियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। उनकी तलाश में टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे। वे अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे।

बतौर राज्यसभा सांसद, 21 जून को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने उन्हें फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया था। कुरियन केरल में भाजपा के सीनियर नेताओं में एक हैं। माना जा रहा है कि हाल ही में केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने की वजह से उन्हें फिर से मौका नहीं मिला।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं शुरु?

प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद ये चर्चाएं चलने लगीं

- **राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की ओर से बैठक के एजेंडा के बारे में अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा गया है। मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल पर भी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।**

नई दिल्ली, 23 जून। केन्द्रीय कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पीएम मोदी की राष्ट्रपति से यह मुलाकात पद्म पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में हुई है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर मोदी कैबिनेट में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति की इस बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही केन्द्र सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद में किसी संभावित बदलाव या फेरबदल को लेकर भी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिर भी, इस मुलाकात को संभावित केन्द्रीय कैबिनेट विस्तार या फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल सभी की नजरें सरकार की ओर से आने वाले किसी आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं।

'म.प्र. में यूसीसी को मुस्लिमों का भी समर्थन'

भोपाल, 23 जून। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सभी जिलों में जन परामर्श बैठकें हो चुकी हैं। नागरिकों के 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुये हैं और 90 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है। यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए सभी जिलों में जन परामर्श बैठकें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राज्य स्तरीय परामर्श बैठक 22 जून को भोपाल में हुई। इसमें सभी आयोगों, विभागों, राजनैतिक दलों और धर्मगुरुओं के साथ पृथक-पृथक बैठकें आयोजित कर मत लिया गया।

ईरान के तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध हटने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उत्पादक देशों पर भी काफी निर्भर है। 2025 में भारत के लगभग आधे कच्चे तेल आयात ओपेक देशों से आए थे। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, यह निर्भरता जोखिम पैदा करती है।

ऐसे में ईरान की वापसी से भारत को सप्लाई का एक और महत्वपूर्ण जरिया मिल सकता है।

2018 में अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लागू होने से पहले, ईरान भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। भारतीय रिफाइनरियां ईरानी कच्चे तेल को उसकी प्रतिस्पर्धी कीमतों, अनुकूल ऋण शर्तों और कुछ अन्य स्रोतों की तुलना में कम माल ढुलाई लागत के कारण पसंद करती थीं। प्रतिबंध लगने से पहले भारत ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था।

प्रतिबंधों ने कई वर्षों तक ईरानी तेल आयात का रास्ता लगभग बंद कर दिया। अब, भले ही यह राहत अस्थायी हो, इससे भारतीय रिफाइनरियों और ईरानी आपूर्तिकर्ताओं के बीच बातचीत फिर शुरू हो सकती है।

क्या भारत फिर से ईरानी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर सकता है? फिलहाल, तुरंत नहीं।

मौजूदा छूट केवल 60 दिनों के लिए है और यह जारी कूटनीतिक वार्ताओं से जुड़ी हुई है। रिफाइनरियां आमतौर पर बड़े पैमाने पर खरीदारी करने से पहले दीर्घकालिक स्पष्टता चाहती हैं।

फिर भी, यह कदम संकेत देता है कि यदि वार्ताएं आगे बढ़ती हैं, तो ईरानी तेल धीरे-धीरे वैश्विक बाजार में लौट सकता है। केवल यह संभावना भी भारत के लिए लाभदायक हो सकती है।

बाजार में अधिक तेल उपलब्ध होने का मतलब आमतौर पर कम कीमतें और खरीदारों के लिए बेहतर सौदेबाजी की शक्ति होता है। भले ही भारत सीधे तौर पर ईरान से तेल खरीद में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी न करे, लेकिन ग्लोबल सप्लाई बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने और आयात लागत कम करने में मदद कर सकती है।

एक और वजह, जिससे भारत इस घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है, वह है होर्मुज़ जलडमरूमध्य। भारत के तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है।

हाल के क्षेत्रीय तनावों ने सप्लाई बाधित होने और तेल की कीमतों में तेज उछाल की आशंकाएं बढ़ा दी थीं। अमेरिका और ईरान समझौते में समुद्री सुरक्षा और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही से जुड़े वादे शामिल हैं।

यदि इस मार्ग से जुड़े जोखिम कम होते हैं, तो यह भारत के लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। भारत का वार्षिक कच्चे तेल का आयात बिल 100 अरब डॉलर से कहीं अधिक है और वैश्विक तेल कीमतों के अनुसार यह काफी बदलता रहता है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मामूली गिरावट भी एक वर्ष में भारत के अरबों डॉलर बचा सकती है। इसी कारण भारतीय नीति-निर्माता प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में होने वाले घटनाक्रमों पर लगातार बारीकी से नज़र रखते हैं। यदि ईरानी तेल की आपूर्ति बड़े पैमाने पर लौटती है और भू-राजनीतिक तनाव कम होते हैं, तो तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इससे भारत को महंगाई नियंत्रित रखने, आयात लागत घटाने और बाहरी आर्थिक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्रियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीपीआई (एमएल) के 2 विधायकों ने भी नाथवानी को वोट दिया। आरजेडी का चौथा वोट अवैध घोषित हो गया।

झामूमो ने सुनिश्चित किया कि उसके प्रत्याशी को आवश्यक 28 वोटों के बजाय 30 वोट मिलें, जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले, जबकि पीरामल नाथवानी, जिनके पास 24 वोट ही थे, को 28 वोट मिल गए और वे राज्यसभा में प्रवेश कर गए। हेमंत सोरेन ने नाथवानी को हार्दिक बधाई दी, लेकिन उन्होंने पराजित कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस इस घटनाक्रम से बेहद नाराज है और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और वाम दलों के बीच दरारें और गहरी हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस झारखंड में गठबंधन सरकार छोड़ने के लिए तैयार है, जिससे भाजपा के लिए रास्ता खुल सकता है, या फिर वह इस अपमान को सहकर आगे बढ़ जायेगी।

अजीबोगरीब नीति है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देवेन्द्र फड़नवीस की भविष्य की नेतृत्व संभावना मजबूत होती, जो आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। इसी तरह, अगर टीएमसी के बागी सांसद भाजपा में शामिल होते, तो इससे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की एक बड़ी और प्रभावशाली छवि बनती।

चूंकि टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के टूटे हुए गुट पहले से ही एनडीए के सहयोगी हैं, इसलिए अब निर्णय लेने की शक्ति अमित शाह के हाथ में है। हालांकि भाजपा लोकसभा में अभी भी अल्पमत में है, लेकिन भाजपा के बजाय एनडीए को मजबूत करने का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। यदि समाजवादी पार्टी में संभावित विभाजन होता है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि टूटने वाले गुटों को अनुप्रिया पटेल के "अपना दल (सोनेलाल)" या ओम प्रकाश राजभर की "सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी" में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एसआईटी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी गठित कर कथित अनियमितता को लेकर लगे आरोपों की जांच करने की मांग की थी। एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरन एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन को शामिल किया गया था। विजय वी पंत और किरन एस ने शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है।

री-नीट परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरह की अन्य सामग्री नहीं मिली है। उससे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उसके भविष्य को देखते हुए उसे जमानत दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से इसके विरोध में कहा गया कि आरोपी अपने अन्तःवस्त्र में मोबाइल छिपाकर लाई थी और परीक्षा में पूछे गए सवालों को एआई के जरिए हल करने के फिराक में थी। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए। अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

गौरतलब है कि इस संबंध में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदायका की केन्द्र अधीक्षक ने 21 जून को बिंदायका पुलिस थाने में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, 2024 की धारा-3 व 10(2), बीएनएस की धारा-318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा-66 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 पद्मविभूषण, 7 पद्मभूषण व 55 पद्मश्री पुरस्कार बांटे

केरल के पत्रकार पी. नारायणन तथा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस को पद्मविभूषण प्रदान किया

नई दिल्ली, 23 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याज्ञनिक, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता आर. माधवन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन सहित, 64 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 55 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह में केरल के प्रख्यात मलयालम पत्रकार पी. नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा तथा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के. टी. थोमस को लोक कार्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति ने मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को उनके लंबे और उत्कृष्ट फिल्मी योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय संगीत जगत की प्रसिद्ध गायिका अलका याज्ञनिक को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

विकास जैफ की प्रतिनियुक्ति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आया है कि "ग्रामीण विकास मंत्री ने इस नियुक्ति के आदेश दिए थे, जैफ खुद आदेश की कॉपी लेकर विभाग में पहुंचे थे।" हैरानी की बात है कि पूरे मामले में जैफ की भूमिका संदिग्ध और विभाग को दिए गए जवाब के विपरीत होने के बावजूद, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जैफ को क्लीन चिट देते हुए मामले को रफा-दफा करने की सिफारिश तक कर डाली। जबकि कमेटी को विपरीत तथ्य मिले थे ऐसे में अब जैफ की इस प्रतिनियुक्ति और उसके बाद हुई जांच की "गोलमोल" रिपोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं।

गौरतलब है कि गत 31 मार्च 2026 को ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े बायोफ्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने आदेश जारी कर विकास जैफ को बायोफ्यूल प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से लगाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश में कहा गया था कि कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर कार्यरत विकास जैफ, स्वयं के विभाग से एनओसी लेकर पद संभालेंगे। ज्ञात रहे कि विकास जैफ फिलहाल राजस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आमेट (राजसमंद) में कार्यरत हैं तथा उनके पास राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दौसा का अतिरिक्त चार्ज भी है।

मजेदार बात यह है कि इस प्रतिनियुक्ति की पत्रावली 30 मार्च को शुरू हुई और 31 मार्च की शाम को नियुक्ति आदेश जारी हो गए। जैसे ही इस नियुक्ति की भनक कौशल उद्यमिता विभाग को लगी तो निदेशक (प्रशिक्षण) मुनीश कुमार शर्मा ने इस नियुक्ति आदेश को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया। उनकी ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विकास जैफ और सुरेन्द्र सिंह राठौड़ दोनों ने ही इस नियुक्ति से पूर्व उनके विभाग से कोई स्वीकृति अथवा अनुमति नहीं ली। ऐसे में यह आदेश विभागीय नियमों के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव नरेश गोकलानी ने सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) विकास जैफ को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था। इस नोटिस में विकास जैफ से तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। उनसे पूछा गया है कि क्या बायोफ्यूल प्राधिकरण में पदस्थापन के लिए विकास जैफ ने कोई आवेदन किया था? यदि आवेदन किया था तो कब और किस माध्यम से अथवा सीधे ही बायोफ्यूल प्राधिकरण में आवेदन किया था? क्या उन्होंने आवेदन से पूर्व कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग से इस संबंध में प्रशासनिक अनुमति प्राप्त की थी? विकास जैफ ने 7 अप्रैल को इस नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि "बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति किए जाने हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया।" शेष 2 बिंदुओं पर उन्होंने जवाब में "लागू नहीं" अंकित किया। जैफ के इस जवाब से असंतुष्ट कौशल उद्यमिता विभाग ने मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने के आदेश 10 अप्रैल को जारी किए। इस कमेटी में बायोफ्यूल प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र कुमार शर्मा, परियोजना निदेशक एवं उप सचिव ईजीएस रतनलाल अटल तथा ग्रामीण विकास विभाग की शासन उप सचिव प्रतिष्ठा पिलानिया शामिल थे। इस राज्य स्तरीय कमेटी ने 16 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह तो स्वीकार किया कि "ग्रामीण विकास मंत्री ने इस नियुक्ति के लिए आदेश दिए थे, पत्रावलियों की प्रतिलिपि लेकर जैफ खुद विभाग में पहुंचे थे।" यह मामला सामने आने के बाद भी जांच कमेटी ने इस गंभीर प्रकरण को यह कहते हुए समाप्त करने की सिफारिश कर डाली कि "विकास जैफ की प्रतिनियुक्ति इस शर्त पर दी गई थी कि वे अपने विभाग से एन.ओ.सी. लाएंगे, चूंकि वे इसमें असमर्थ रहे, जिस पर प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश हो चुके हैं, अब प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।"

जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि विकास जैफ ने ग्रामीण विकास मंत्री को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके बायोफ्यूल प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति करने का निवेदन किया था, जिस पर मंत्री ने 30 मार्च को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में "अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही" करने के निर्देश दिए थे। मंत्री के निर्देशों की पालना में इस प्रार्थना पत्र को पीयूसी बनाकर उसी दिन विभागीय ऑनलाइन पत्रावली पर भेज दिया गया।

नाम परिवर्तन कई बार भारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नरसंहार की योजना और उसका क्रियान्वयन तत्कालीन अविभाजित बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने किया था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने और देश के विभाजन की मांग के समर्थन में ग्रेट कलकत्ता किलिंग को अंतिम चेतावनी के रूप में देखा जाता है।

बाद में पाकिस्तान बनने के बाद, हुसैन शहीद सुहरावर्दी उस देश के प्रधानमंत्री भी चुने गए। सड़क का नाम बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि कई दशकों बाद कोलकाता उस बोझ से मुक्त हुआ है, जिसमें उसे ऐसे राजनीतिक नेता का नाम ढोना पड़ रहा था, जिसने बंगाल में नरसंहार करवाया था।

हालांकि नाम बदलने के तुरंत बाद यह तथ्य सामने आया कि सड़क का नाम उस विवादास्पद राजनेता के चाचा के नाम पर रखा गया था। बताया गया कि इस एवेन्यू का नाम हसन सुहरावर्दी के नाम पर था, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम कुलपति थे। हसन सुहरावर्दी एक चिकित्सक थे। वे शिक्षाविद और सैनिक भी थे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में बंगाल के लैफ्टिनैंट गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर क्रांतिकारी बीना दास ने हमला किया था।

उस हमले के दौरान, हसन सुहरावर्दी ने स्टेनली जैक्सन की जान बचाई थी। स्वाभाविक रूप से इसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया और कई महत्वपूर्ण पद दिए गए, जिनमें कोलकाता विश्वविद्यालय का शीर्ष पद भी शामिल था। उनके सम्मान में कोलकाता नगर निगम ने, जिसके मेयर कभी सुभाष चंद्र बोस भी रह चुके थे, पार्क सर्कस से हसन सुहरावर्दी के निवास की ओर जाने वाली सड़क का नाम उनके नाम पर रखा था। कई लोगों का कहना था कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने का मतलब था, "बंगाल के कसाई" का नाम हटाना। फिर भी, सुहरावर्दी नाम अपने साथ ऐसी कड़वी ऐतिहासिक स्मृतियां लेकर आता है, जिनसे उसे अलग करना मुश्किल है।

सड़कों, गलियों और इलाकों के नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। राज्य के वामपंथी शासन के दौरान हैरिंगटन स्ट्रीट, जहां कोलकाता में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थित है, का नाम बदलकर हो ची मिन्ह सरणी कर दिया गया था। यह कदम अमेरिका के प्रति राजनीतिक असहमति जताने के रूप में देखा गया था।

आज वियतनाम और उससे जुड़ी कई बातें अमेरिकियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बंगालियों को सुहरावर्दी स्वीकार्य नहीं है, और आम तौर पर लोग इस नए नामकरण से संतुष्ट दिखाई दिए।

नई सरकार के लिए पार्क सर्कस भी एक संवेदनशील इलाका है। भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही आदेश जारी किया गया कि कोई भी धार्मिक स्थल प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगा।

इसके बाद पार्क सर्कस में बड़ी संख्या में मुस्लिम एकत्र हो गए और उन्होंने पुलिस चौकियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

इसके अलावा कुछ वाहनों और अन्य संपत्तियों में आग भी लगा दी गई।

पुलिस को कानून-व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया गया और मात्र दो घंटे के भीतर स्थिति नियंत्रण में ले ली गई। उत्तेजित मुसलमानों की भारी भीड़ को पीछे खदेड़ दिया गया।

नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कड़ा संदेश दिया कि हमले और संपत्ति का नुकसान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में गए और कहा कि यदि ऐसे हमले दोबारा हुए, तो वे उनके लिए सबसे सख्त पुलिस मंत्री साबित होंगे। इस संदेश का अपेक्षित प्रभाव पड़ा और पार्क सर्कस क्षेत्र में शांति लौट आई। यह स्थिति तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हो रही घटनाओं से बिल्कुल उलट थी, जब पुलिसकर्मियों को बुरी तरह पीटा जाता था और वे हमलावरों से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढ़ते थे। बंगाल में हालात बदल चुके हैं, और काफी हद तक बदल चुके हैं।

प्रशासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908